ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-2* May- 2020
Anthology : The Research

उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में अनुसूचित जाति की दिशा और दशा

Scheduled Caste Direction and Condition in Uttar Pradesh's Rampur District

Paper Submission: 15/05/2020, Date of Acceptance: 23/05/2020, Date of Publication: 24/05/2020

मनोरम
फैकल्टी,
अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
चौखुटिया (अल्मोडा)
उत्तराखंड, भारत

सारांश

आर्थिक विकास की पहली आवश्यकता सामाजिक विकास है। भारत में प्रारम्भ से ही सामाजिक विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। समाज की वर्ण व्यवस्था जब से जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई तब से भारतीय समाज में अनेक दोष उत्पन्न हो गये। हिन्दू समाज की रचना चार वर्गों – ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित है। इन चार वर्णों में अंतिम अर्थात् शूद्र वर्ग अनुसूचित जाति के नाम से पुकारा गया और इसे समाज में रहने, अपना विकास करने तथा कल्याण के वह अवसर उपलब्ध नहीं कराये गये जो अन्य जातियों को सामाजिक दशा बिगड़ती गई। सामाजिक दोषों ने अनुसूचित जाति के लोगों में उद्यमशीलता के गुण को विकसित नहीं होने दिया जिससे इस वर्ग की उत्पादकता और कुशलता सीमित हो गई। अनुसूचित जाति के परिवार घोर निर्धनता और अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने को विवश हो गये। निर्धनता और सामाजिक उपेक्षा के कारण अनुसूचित जाति के लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति व युवाओं में वेश्यावृत्ति, लूटमार तथा अन्य अपराधों में संलग्नता का दोष उत्पन्न हो गया। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थता अनुसूचित जाति के अटकाव का कारण बनी। इस सब दूषित वातावरण ने अनेक समाज सुधारकों को जन्म दिया जिनमें सर्वप्रमुख डॉ0 भीमराव अम्बेडकर थे जिनका जन्म महाराष्ट्र में अस्पृश्य कही जाने वाली महार जाति में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इस समाज सुधारक के विचारों से राजनीतिज्ञ भी प्रभावित हुये। फलस्वरूप अनुसूचित जाति के आर्थिक–सामाजिक कल्याण हेतु राजनैतिक प्रयास प्रारम्भ हुए। अनुसूचित समाज में भी जागरूकता आयी और वह सरकारी प्रयासों का लाभ उठाने हेतु उद्यत हुआ। केन्द्र तथा राज्य सरकार ने समाज के निर्बल–निर्धन वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान एवं समृद्धि हेतु अनेक योजनायें प्रारम्भ की जिन्होंने अनुसूचित जाति के आर्थिक–सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश जोकि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, में 71 अनुसूचित जातियाँ निवास करती हैं। इस प्रदेश में कई बार ऐसी सरकारों का गठन हुआ है जिन्होंने अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा की है और उनकी समृद्धि हेतु पृथक से समाज कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम स्थापित किया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु अनेक आर्थिक–सामाजिक योजनायें एवं कार्यक्रम लागू हैं जैसे – शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, बुक बैंक योजना, प्रशिक्षण योजना, औद्योगिक अस्थानों का संचालन, उन्नयन बस्तियों की स्थापना, आश्रम पद्धति के विद्यालयों का संचालन, छात्रावास स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुर्नवास योजना, स्वतः रोजगार योजना आदि।

The first requirement for economic development is social development. Right from the beginning, social development was not given proper attention. Ever since the Varna system of the society changed into the caste system, many defects have arisen in Indian society. The composition of Hindu society is based on four classes - Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. The last of these four varnas, namely the Shudra class, was called the Scheduled Caste and it did not provide the opportunities for living, development and welfare in the society which worsened the social condition of other castes. Social defects did not allow the quality of entrepreneurship to develop among the Scheduled Castes, which limited the productivity and efficiency of this class. Scheduled caste families were forced to live a life of extreme poverty and scarcity. Poverty and social neglect led to the tendency of the Scheduled Castes to commit suicide and the youth to engage in prostitution, robbery and other crimes. The inability to fulfill the basic necessities of life led to the attachment of Scheduled Castes. All this polluted environment gave birth to many social reformers including Dr. Bhimrao Ambedkar, the foremost who was born in Maharashtra on 14 April 1891 in the Mahar caste called untouchables. Politicians were also impressed by the views of this social reformer. As a result, political efforts started for the economic and social welfare of scheduled castes. Awareness also came in the scheduled society and it was determined to take advantage of government efforts. The Central and State Government have initiated several schemes for the upliftment and prosperity of the weaker sections of the society and scheduled caste tribes, which have contributed significantly to the economic-social development of the scheduled castes. Uttar Pradesh, which is India's largest state by population, has 71 scheduled castes. Many times governments have been formed in this state which have protected the interests of Scheduled Castes and have set up separate Social Welfare Department and Scheduled Caste Finance and Development Corporation for their prosperity. Currently, many economic-social schemes and programs are implemented for the welfare of scheduled castes in Uttar Pradesh - Scholarship for education, Book bank scheme, Training scheme, Operation of industrial places, Establishment of Upgradation settlements, Operating of ashram system schools, Hostel. Swachkar Vimukti and Rehabilitation Scheme, Self Employment Scheme etc.

मुख्य शब्द : अनुसूचित जाति, संविधान, अस्पृश्य, वर्ण–व्यवस्था, सामाजिक, दिशा, आर्थिक विकास, समंक।

Scheduled Caste, Constitution, Untouchables, Varna-system, Social, Direction, Economic Development, Sank.

प्रस्तावना

भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहॉ अनेकता में एकता व्याप्त है। भारत में विभिन्न जातियॉ ,धर्म और भाषाओं वाले लोग इस देश में एक साथ निवास करते है। भारत में जाति और भाषाओं के आधार पर भिन्न–भिन्न प्रकार के समुदाय अथवा वर्णो को देखा गया है। भारतीय संविधान के समाजवादी दृष्टिकोण में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार,समान कार्य समान वेतन का अधिकार तथा किसी भी धर्म को मानने का अधिकार प्राप्त है। भारत में वर्ण–व्यवस्था के अर्न्तगत अनुसूचित जाति के लोगो के सामाजिक–आर्थिक, राजनैतिक उत्थान के लिए स्वतत्रंता के पश्चात भारत में सरकारों, गैर–सरकारी संगठनो तथा कई समाज सुधारको द्वारा अनेक महत्वपुर्ण प्रयास किये गये है। इन प्रयासो में सरकारो द्वारा नौकरीयो में आरक्षण एवं सहायता कार्यक्रम उल्लेखनीय है। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु अनेक प्रयास किये गये है। किन्तु यह सभी प्रयास ऊट के मुहॅ में जीरे के समान है। प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में अनुसूचित जाति की दिशा और दशा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था मे जाति प्रथा एक प्रमुख दोष है। इस प्रथा के अनुसार अनुसूचित जाति समाज की सबसे निचली जाति मानी गई है। समाज सुधारकों के प्रयासों तथा शिक्षा के विस्तार ने अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु आवश्यक वातावरण निर्मित किया है। सरकारी स्तर पर भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं विभिन्न सरकारों ने अनुसूचित जाति के आर्थिक–सामाजिक विकास हेतु समय–समय पर अनके योजनायें प्रारम्भ की है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भी इन योजनाओ का कमोवेश कुछ लाभ मिला है किन्तु आज भी इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। इनमें से कुछ योजनायें ऐसी भी हैं जो यद्यपि समाज के सभी वर्गों को उपलब्ध है किन्तु उनमें अनुसूचित जाति को प्राथमिकता प्रदान की गई है। ऐसी ही एक योजना स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना है जिसका अध्ययन रामपुर जनपद की अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में इस शोध पत्र के अतंर्गत किया गया है। आर्थिक विकास की पहली आवश्यकता सामाजिक विकास है भारत में प्रारम्भ से ही सामाजिक विकास पर उचित ध्यान नही दिया गया। समाज की वर्ण व्यवस्था जब से जाति व्यवस्था में परिवर्तित हई तब से भारतीय समाज में अनके दोष उत्पन्न हो गये। हिन्दू समाज की रचना चार वर्णो – ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित है। इन चार वर्णों में अंतिम अर्थात् शूद्र वर्ग को अनुसूचित जाति के नाम से पुकारा गया और इसे समाज में रहने, अपना विकास करने तथा कल्याण के वह अवसर उपलब्ध नहीं कराये गये। अनुसूचित जाति के परिवार घोर निर्धनता और अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने को विवश हो गये। निर्धनता और सामाजिक उपक्षा के कारण अनुसूचित के लोगो में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ी। कुछ युवाओं में वश्यावृत्ति, लटूमार तथा अन्य अपराधों में सलंग्नता का दोष उत्पन्न हो गया। जीवन की मलूभतू आवश्यकताओं को पर्णू करने में असमर्थता अनुसूचित जाति के अटकाव का कारण बनी। इस सब दूषित वातावरण ने अनके समाज सुधारकों को जन्म् दिया जिनमें सर्वप्रमुख डॉ0 भीमराव अम्बेडकर थे, जिनका जन्म् महाराष्ट्र में अस्पृश्य कही जाने वाली महार जाति में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था।

इस समाज सुधारक के विचारों से राजनीतिज्ञ भी प्रभावित हुये। फलस्वरूप अनुसूचित जाति के आर्थिक–सामाजिक कल्याण हेतु राजनैतिक प्रयास प्रारम्भ हए। अनुसूचित समाज में भी जागरूकता आयी और वह सरकारी प्रयासों का लाभ उठाने हेतु उद्यत हुआ। केन्द्र तथा राज्य सरकार ने समाज के निर्बल–निर्धन वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान एवं समृद्धि हेतु अनके योजनायें प्रारम्भ की जिन्हानें अनुसूचित जाति के आर्थिक–सामाजिक विकास में महत्वपर्ण यागेदान दिया है। उत्तर प्रदेश जोकि जनसख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, में 71 अनुसूचित जातियाँ निवास करती है। इस प्रदेश में कई बार ऐसी सरकारों का गठन हुआ है जिन्हानें अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा की है और उनकी समृद्धि हेतु पृथक से समाज कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति वित्त एव ंविकास निगम स्थापित किया है।

शोध का स्वरूप एवं प्रकृति

प्रस्तुत शोध कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसके अंतर्गत जनपद रामपुर में अनुसूचित जाति के आर्थिक–सामाजि उन्नयन के सन्दर्भ में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना से सम्बन्धित द्वितीयक समंकों एवं प्राथमिक समंकों का उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों के द्वारा विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं। चूंकि प्राथमिक समंक भी प्रयोग किये गये हैं इसलिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। समंक संकलन हेतु स्वनिर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

शोध कार्य के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के मुख्य उद्देश्य निम्न लिखित है–

1. जनपद रामपुर की जनांकिकीय संरचना का अध्ययन करना ।
2. जनपद रामपुर की अनुसूचित जातियों का सामाजिक विश्लेषण करना।
3. जनपद रामपुर की अनुसूचित जातियों के राजनैतिक स्वरुप का अध्ययन करना।
4. जनपद रामपुर की अनुसूचित जातियों का आर्थिक विश्लेषण करना।
5. केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के उन्नयन हेतु संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
6. अनुसूचित जातियों की मुख्य समस्याओं का अवलोकन करना ।

7. समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन क्षेत्र का चुनाव

रामपुर जनपद एक अविकसित जनपद है क्योंकि इसकी सभी सीमाएं किसी न किसी नदी से लगी होने के कारण बरसात के मौसम में क्षेत्र को प्रभावित करती रहती है। विकास की दृष्टि से क्षेत्र में निवास कर रहें अनुसूचित जाति के लोग अत्यंत पिछड़े हुए है। अतः यह अययन जनपद रामपुर की सीमाओं तक सीमित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु अनके आर्थिक–सामाजिक योजनायें एवं कार्यक्रम लागू हैं जैसे –शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, बुक बैकं योजना,प्रशिक्षण योजना, औद्योगिक संस्थानों का सचांलन, उन्नयन बस्तियों की स्थापना, आश्रम पद्धति के विद्यालयों का सचांलन, छात्रावास स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुर्नवास योजना, स्वतः रोजगार योजना आदि। राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनायें थीं। जो सरकारी सहयोग के साथ चलायी जा रही है जिनमें प्रधानमंत्री योजना, जवाहर रोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना तथा स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रमुख है।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना रोजगार की सबसे बड़ी एवं प्रभावशाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित आर्थिक सामाजिक स्तर वाले लागों को स्वराजेगार के अवसर उपलब्ध है चूकि अनुसूचित जाति के लागे सामान्यता निम्न आर्थिक–सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसलिए उनके लिए इस याजेना का अत्यधिक महत्व है योजना में भी अनुसूचित जाति को प्राथमिकता प्रदान की गई है यह योजना अन्य सरकारी योजनाओं की भाति
आकंड़ों का खेल है या फिर वास्तव में निर्बल वर्ग को सहारा देने में सफल हुई है यह एक महत्वपर्ण प्रश्न है।

निष्कर्ष व सुझाव

उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में अनुसूचित जाति की दशा देश के अन्य भागों की अपक्षा अधिक खराब रही है इसलिए इस जनपद के अनुसूचित वर्ग के लिए स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एक सुरक्षा छतरी सिद्ध होगी ऐसा विचार था। वास्तव में यह योजना अपने उद्दश्ेय में कहा तक सफल हुई अर्थात जनपद के अनुसूचित वर्ग के अनार्थिक समृद्धि में इस याजेना की भूमिका रही है और उसे किस प्रकार अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आजादी के पश्चात् भारत के संविधान में दलित हितों के संरक्षण के लिए ये व्यवस्था की गई है यद्यपि उन्हें लागू करने की प्रक्रिया आधी–अधूरी हो रही है। फिर भी इनकी वजह से दलितों के एक तबके को फायदा हुआ है। अस्तित्व के लिए उनकी लडाई आसान हुई है। शासन को इन कदमो की वजह से आज दलितो (अनुसूचित जाति) की हर जगह नुमाइदंगी होती है। राजनैतिक क्षेत्र (संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों) में ये संख्या सुनिश्चित है।हालांकि, अकादेमिक और ब्यरोक्रेसी के विकास में उनकी संख्या घट रही है। करोबार के क्षेत्र में उनकी संख्या घट रही है। करोबार के क्षेत्र में कई दलितो ने अपना सिक्का जमाया है। जिससे प्रतीत होता है कि दलितो के एक तबके ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी ज्यादातर दलित उसी हालत में है, जिस स्थिति में वो आज से एक सदी पहले थे। जिस तरह से आरक्षण की नीति बनाई गई है,ये उन्ही लोगों को फायदा पहुँचाती आ रही हैं, जो इसका लाभ लेकर आगे बढ चूके है।ये दलितों की कुल आबादी का महज 10 फीसदी हैं।

डॉ भीमराव आम्बेडकर ने कल्पना की थी कि आरक्षण की मदद से आगे बढने वाले यह दलित, अपने समाज (बिरादरी) के दुसरे लोगो को भी समाज के दबे–कुचले वर्ग से बाहर लाने में मदद करेगे, किन्तु तरक्कीयाफता दलितों का ये तबका, दलितों में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तौर पर खुद को ऊँचे दर्जे का समझने लगा और अनुसुचित जाति के लोगो को नजरअंदाज करने लगा। इस वर्ग के लोगो के उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि इन्हे रोजगारपूरक शिक्षा प्रदान की जाये तथा सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को धरातल पर शत् प्रतिशत कियान्वित किया जाये।

References

1. *Ambedkar, B.R.: What congress and Gandhi have done to untouchables.*
2. *Bailey, F.G : Caste and Economic Frontier.*
3. *Chandra, Sushil : Social work in Uttar Pradesh.*
4. *Ghurye, G.S.: Caste, Class and Occupation, 1961.*
5. *Jagannadham V.: Administration of Welfare Programme for Weaker Sections.*
6. *Justice Iyer V. R. Krishna: Dr. Ambedkar and the dalit Literature.*
7. *Mahajan, R.K. : Indian History.*
8. *Majumdar, A. M : Social Welfare in India.*
9. *Rajgopal, V: Schedule Caste of Rural India; Problems and prospects.*
10. *Census of India and U.P {Since 1951 to 2011}*
11. *District Economic Diary of Rampur Since 1951 to 2011*